अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की सूची में जातियों की नई श्रेणियों का शामिल किया जाना

1345. **श्री अजीत जोगी** : क्या कल्याण मंत्री 5 मई, 1989 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1346 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन करने का प्रस्ताव सरकार के पास किस चरण में लंबित पड़ा हुआ है ;

(ख) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है; और

(ग) इन सूचियों में संशोधन करने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदंड और मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं और उनका ब्यौरा क्या है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में व्यापक संशोधन करने के बारे में एक मंत्रिमंडल नोट तैयार किया गया था तथा पिछली सरकार के मंत्रिमंडल को उनके विचार के लिए प्रस्तुत किया गया था। मंत्रिमंडल की 26.12.1988 को हुई बैठक में, मामले को आस्थगित रखा गया, वर्तमान सरकार इस बारे में प्राप्त किए गए सभी प्रस्तावों, सिफारिशों, सुझावों आदि की नए सिरे से जांच कर रही है। फिर भी, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की विद्यमान सूचियों में कोई संशोधन संविधान के अनुच्छेद 341(2) तथा 342(2) को ध्यान में रखते हुए केवल संसद के अधिनियम के माध्यम से किया जाना है।

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में समुदायों को शामिल करने के लिए निम्नलिखित मानदण्डों को अपनाया गया है:—

अनुसूचित जातियां

अस्पृश्यता की परम्परागत प्रथा के कारण उत्पन्न सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक अत्यन्त पिछड़ापन ;

अनुसूचित जनजातियां

प्राचीन विशेषताओं के लक्षण विशिष्ट सांस्कृतिक भौगोलिक एकाकीपन, सामान्य रूप से समुदाय के साथ सम्पर्क करने में संकोच तथा पिछड़ापन।

आधुनिक निष्कर्षण सुविधाओं की कमी के कारण खाद्य तेलों की हानि

1346. **श्री राम नरेश यादव** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिलहनों से तेल निकालने के लिए परिष्कृत और आधुनिक प्रौद्योगिकी के अभाव में इस समय प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में खाद्य तेल की बर्बादी हो रही है ;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रकार से हो रही हानि का कोई मूल्यांकन किया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने एक परिष्कृत मशीन का निर्माण करने के लिए एक डिजाइन तैयार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उक्त मशीन के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजना क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) तेलों के उपलब्ध स्रोतों का संतोषजनक ढंग से उपयोग न कर पाने के लिए कई बातें जिम्मेदार हैं, जैसे उन्हें एकत्र कर में आने वाली कठि-

नाई, उचित भंडारण की सुविधा का अभाव, आधुनिक संसाधन सुविधाओं का न होना आदि।

(ख) और (ग) इस प्रकार हुए घाटों का वैज्ञानिक आधार पर कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा प्रतिदिन 10 मी. टन की क्षमता का एक एक्स्पेलर डिजाइन तथा निर्मित किया गया है। खली से प्राप्त होने वाले तेल का प्रतिशत पारम्पारिक एक्स्पेलर की तुलना में 2% अधिक है। तथापि, वाणिज्यिक पैमाने पर एक्स्पेलर की उपयुक्तता और आर्थिक रूप से इसकी व्यवहार्यता, प्रमाणित नहीं है इसके प्रदर्शन हेतु सहायता दी जा रही है।

असिंचित भूमि के संबंध में अनुसंधान और अन्वेषण

1347. **श्री राम नरेश यादव** : क्या कृषि मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि अनुसंधान तथा अन्वेषण संस्थानों को तीन चौथाई कृषि भूमि के बारे में जो सिंचाई के लिए या तो पूर्णतया वर्षा पर निर्भर है अथवा उसमें बिना सिंचाई के ही कृषि उत्पादन किया जाता है, अनुसंधान तथा अन्वेषण कार्य प्रारम्भ करने संबंधी कोई निर्देश दिये हैं ताकि कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई प्रगति हुई है ;

(ग) यदि हां, तो उस प्रगति के को साधारण किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) जी, हां।

(ख) अखिल भारतीय बारानी खेती समन्वित अनुसंधान प्रयोजना के 23 सहकारी केन्द्रों और अन्य फसल सुधार प्रायोजनाओं के तहत किये गये अनुसंधान के फल-स्वरूप बड़े पैमाने पर अपनाये जाने के लिए सुधरी बारानी खेती की तकनीकें मुहैया कराई गयीं।

(ग) हां।

(घ) बारानी खेती के लिए राष्ट्रीय जलसंभर विकास कार्यक्रम केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना के रूप में शुरू किया गया है। इसके अन्तर्गत 99 जिलों की 9.28 लाख हैक्टर भूमि आएगी। सुधरी बारानी खेती पद्धतियों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों द्वारा चलाये जाने वाले विस्तार कार्य-कलाप का एक अंग हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के तकनीकी सहयोग से 47 स्थानों पर आदर्श जलसंभरों के रूप में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन प्रायोजनायें तैयार की गई हैं।

Setting up of Market intervention Fund

1348. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Miniter of AGRICULTURE be pleased to state;

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to set-up a Rupees 30 crores Market Intervening Fund; and

(b) if so, what are the main objectives thereof ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI DEVI LAL) (a) and (b). In view of the speculative nature of the edible oil trade provision has been made for creation of a market intervention fund to be built by the National Dairy Development Board to meet possible losses in market intervention operations. This fund would be created from the surpluses of market intervention ope-